दिल्ली, उ0प्र0, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एवं राजस्थान में प्रसारित।

गुरुकृपा दर्पण

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

UTTHIN/2022/85670

डाक सं० UA/DO/DON/02/2024-2026

वर्ष : 04 | अंक : 30 | हरिद्वार | शनिवार, 9 अगस्त, 2025 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 4

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा

देहरादून। सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पाबौं विकासखण्ड के आपदा प्रभावित गांवों में जाकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मिलकर अपनी संवदेनाएं व्यक्त कर राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया। मंत्री डॉ. रावत ने पाबौं ब्लॉक के सर्वाधिक प्रभावित सैंजी, बांकुड़ा, नौठा बाजार व बुरांसी गांव में आपदा से जान-माल के नुकसान पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हुये पीड़ितों को पूरी संवेदना के साथ ढ़ांढस बंधाया। पीड़ितों की समस्याओं को सहानुभूति और करुणा के साथ सुनते हुये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विपदा की इस घड़ी में आपके साथ खड़ी है और सभी जरूरी राहत एवं पुनर्वास कार्यों प्रतिबद्धता के साथ किये जा रहे हैं। डॉ. रावत ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय भवन, दुकानें व गौशालाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं जबकि कई घर व दुकान मलबे में दबे हैं। क्षेत्र की सड़कें, बिजली, पेयजल एवं संचार सेवाएं बाधित हैं। जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दे दिये गये हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिये भोजन, चिकित्सा व अन्य आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा है। डॉ. रावत ने कहा कि प्रभावितों का विस्थापन व पुनर्वास सरकार की शीघ्र प्राथमिकता में है, इसके लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी गठित की गई है जो नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजेगी ।

धराली से रेस्क्यू कर 19 लोगों को ऋषिकेश में ठहराया

ऋषिकेश। धराली आपदा में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपदा ग्रस्त क्षेत्र से लोगों को रेस्क्यू कर पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट और इसके बाद ऋषिकेश और संबंधित गंतव्य स्थलों पर भेजा रहा है। ऋषिकेश में प्रशासन ने आपदा क्षेत्र से रेस्क्यू लोगों के लिए तीन स्थानों पर ठहरने के इंतजाम किए हैं। इन स्थानों पर पांच सौ लोगों के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था भी प्रशासन ने की है। आपदा प्रभावित 19 लोगों को ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में ठहराया गया है। एसडीएम योगेश मेहरा के मुताबिक ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित कबीर चौरा आश्रम में 250, जयराम आश्रम में 150 और चारधाम ट्रांजिट एवं पंजीकरण केंद्र में 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहां 500 लोगों के लिए भोजन समेत आवश्यक इंतजामों को दुरुस्त रखने के लिए तीन सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नामित कर दिए गए हैं, जिनमें ट्रांजिट केंद्र में पीडब्ल्यूडी के ईई बीएन द्विवेदी, जयराम आश्रम में जल निगम के ईई संजीव कुमार वर्मा और कबीरचौरा आश्रम की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के ईई दीक्षांत गुप्ता को सौंपी गई है। एसडीएम ने बताया कि गुरुवार दोपहर तक 19 लोगों को धराली से रेस्क्यू कर ट्रांजिट केंद्र में ठहराया गया है। सभी का ट्रांजिट केंद्र में संचालित अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। इनमें ज्यादातर घायलों के परिजन और आपदा ग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित लोग शामिल हैं।

शिक्षा विभाग में आपदा को देखते हुए छुट्टियों पर लगाई रोक

देहरादून। शिक्षा विभाग ने आपदा को देखते हुए अफसरों, शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए हैं। छात्र-छात्राओं को भी स्कूल को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर एकत्रीकरण नहीं करने आदेश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय में बुधवार को अफसरों के साथ आपदा में स्कूलों, छात्राओं कौर शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर बैठक की थी। बैठक के बाद शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने छुट्टियों पर रोक के आदेश जारी किए। दीप्ति सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक अपने-अपने तैनाती स्थल पर बने रहेंगे। जनहित और कार्मिकों की सुरक्षा को देखते हुए कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारी से एक स्तर ऊपर अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही अवकाश मिलेगा। इधर, विभाग ने स्कूलों के लिए आपदा से बचाव को लेकर एसओपी जारी कर दी है। एसओपी में यह स्पष्ट किया गया है कि छात्रों को स्कूल से बाहर किसी दूसरे स्थान पर किसी भी गतिविधि के लिए नहीं जुटाया जाए। स्थानीय स्तर के अलावा विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर होने वाले छात्रों के एकत्रीकरण को फिलहाल रोकने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षकों के स्कूलों से दूर शहरों से आवागमन पर सख्ती विद्यालयी शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती की ओर से जारी एसओपी में शिक्षकों को स्पष्ट आदेश किए गए हैं कि वह स्कूल के सबसे नजदीकी बसावट में ही अपनी आवासीय व्यवस्था करें। स्कूल से ज्यादा दूरी से आने-जाने वाले शिक्षकों को तय नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

गुरुकृपा दर्पण (राष्ट्रीय समाचार पत्र) को आवश्यकता है उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए ब्यूरो चीफ, कैमरा मैंन, संवादाताओं की। सम्पर्क करें – 9410731129, 9548880101

आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष में एक माह का वेतन : डॉ अग्रवाल

जतिन शर्मा

इस दौरान उत्तरकाशी के धराली गांव में आपदा से हुए नुकसान व जान गवाने वाले के प्रति संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई

ऋषिकेश। पूर्व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में आई आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक माह का वेतन देने की घोषणा की है। ऐसा करने पर पूर्व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बार फिर यह जता दिया है कि उत्तराखंड और यहाँ के लोग उनके दिल में बसते हैं और उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। इस अवसर पर डॉ अग्रवाल ने कहा है कि उत्तरकाशी के धराली गांव में आई भीषण आपदा से जन-धन की हानि अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। पूर्व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस कठिन समय में देशभर की संवेदनायें प्रभावित परिवारों के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत बचाव अभियान में है। पूर्व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, अपने एक माह के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में अर्पित करने की घोषणा करता की। उन्होंने सभी उत्तराखंडवासियों से भी अपील की है कि इस विपदा की घड़ी में आगे आकर पीड़ितों की हरसंभव सहायता करें। जिससे हम सब मिलकर इस संकट का सामना कर सके।

अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

देहरादून। उत्तरकाशी जिले के धराली में प्राकृतिक आपदा को लेकर अगर कोई अफवाह फैलाता है तो पुलिस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करेगी। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहने की अपील करते हुए ऐसे लोगों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने का अनुरोध किया है। धराली आपदा को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और वीडियो के माध्यम से झूठी सूचनाएं देकर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपदा की इस कठिन घड़ी में लोगों के बीच भय, भ्रम और अराजकता फैलाने वाली गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

सम्पादकीय

उद्योगों को प्रोत्साहन

सम्पादक – देवेन्द्र जौहरी

टिकाऊ वस्त्र इको-सिस्टम के निर्माण के लिए ग्रामीण हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टरों को सहायता देना महत्वपूर्ण है। ये क्लस्टर भारतीय शिल्पकला की उन जीवंत परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें परिवारों और समुदायों द्वारा पीढ़ियों से कायम रखा गया है। निजी क्षेत्र और सामाजिक उद्यमों ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। उनका कार्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के साथ नवाचार, स्थानीय स्रोत,रि-साईकिलिंग और अप-साईकिलिंग, तथा पारंपरिक प्रथाओं के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने तक फैला हुआ हैये प्रयास सहयोग के माध्यम से कारीगर समुदायों को सशक्त बनाने, शिल्पकारों और डिजाइनरों के बीच साझेदारी बनाने, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 और अमेरिका के सांता फे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला बाजार जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भारतीय शिल्पकारों की हालिया भागीदारी उनकी अनुकूलनशीलता और वैश्विक अपील को दर्शाती है। भारत सरकार अनेक योजनाओं और पहलों के माध्यम से वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र (टेक्सटाइल इको-सिस्टम) का समर्थन करती है।

राहत एवं बचाव कार्य हेतु एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग :आदेश चौहान

जतिन शर्मा

हरिद्वार। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने दिनांक 5.8.2025 को उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा जिसमें बादल फटने की घटना से भारी जान और माल का नुकसान हुआ है इसको देखते हुए रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य हेतु अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर सहयोग किया है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने घटना पर दुख

व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद एवं व्यथित करने वाली है। प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह आपदा प्रभावित आम जनमानस के लिए इस कठिन समय में खड़े हों। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि इस भीषण प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं राहत एवं विचार कार्य के लगातार समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां राहत बचाव एवं पुनर्वास के कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हैं।

बचाव एवं राहत कार्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : माला राज्य लक्ष्मी शाह

नई टिहरी। टिहरी लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने उत्तरकाशी जनपद के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में हताहत हुई व्यक्तियों एवं उनके परिजनों की प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों की शीघ्र कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि हम सम्बंधित अधिकारियों, जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी संपर्क किया। उन्हें भी त्वरित कार्यवाही के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को भी मोबाइल टीमों के साथ और अस्पताल में उचित व्यवस्था बनाए रखने के साथ तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी और गृहमंत्री अमितशाह ने भी फोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस दुखद घटना पर राहत एवं बचाव कार्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही लगातार निगरानी बनाये हुऐ हैं। सांसद ने कहा कि मैं इस संकट की घड़ी में स्थानीय लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और आप जनमानस से भी अपील करती हूं, कि वे भी इस आपदा की दु:खद घड़ी में राहत एवं बचाव कार्यों में जुट कर प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाएं। यह समय आपदा प्रभावित लोगों को उचित स्थान पर पहुंचाने और सहयोग करने का है।

शांतिकुंज से उत्तरकाशी आपदा राहत हेतु राहत दल रवाना

जतिन शर्मा

हरिद्वार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को बादल फटने की भीषण आपदा में कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इस दुःखद अवसर पर संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए संस्था प्रमुख शैलदीदी की अध्यक्षता में शांतिकुंज में आपदा प्रबंधन दल की बैठक हुई और त्वरित रूप से एक विशेष आपदा राहत सर्वे दल को उत्तरकाशी के लिए भेजने पर निर्णय हुआ। शांतिकुंज की शैलदीदी के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद लेकर आपदा प्रबंधन से प्रशिक्षित सदस्य इन्द्रजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम उत्तरकाशी के लिए 6 अगस्त को रवाना हुई। शैलदीदी ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तरकाशी में आई इस प्राकृतिक आपदा से पूरा गायत्री परिवार चिंतित है। हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि हताहतों को शांति एवं शोकाकुल परिवारों को धैर्य प्रदान हो। शांतिकुंज इस संकट की घड़ी में आपदा प्रभावित परिवार के साथ खड़ा रहेगा। यूरोप प्रवास पर गये देसंविवि के प्रतिकुलपति डॉ चिन्मय पण्ड्या ने अपने भेजे गये संदेश में घटना पर दुःख व्यक्त किया। उन्होंने शांतिकुंज के आपदा प्रबंधन दल को पीड़ितों तक हरसंभव सहयोग करने हेतु मार्गदर्शन दिया। व्यवस्थापक योगेन्द्र गिरि ने बताया कि राहत दल स्थानीय प्रशासन एवं परिजनों के सतत संपर्क में है। पीड़ितों की आवश्यकताओं का आकलन कर सहायता पहुँचाई जाएगी। योजना के अनुसार उत्तरकाशी में त्वरित रूप से एक अस्थायी भोजनालय स्थापित किया जाएगा तथा जरूरतमंदों को कपड़े, बर्तन, सूखा राशन, नाश्ता जैसी मूलभूत सामग्री वितरित की जाएगी। शांतिकुंज का आपदा प्रबंधन दल पूर्व में केदारनाथ, पिथौरागढ़, गुजरात भूकंप, नेपाल भूकंप जैसी आपदाओं में भी सक्रिय सेवा दे चुका है। एक बार फिर शांतिकुंज ने सेवा, संवेदना और समर्पण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तरकाशी के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति एवं सहायता का हाथ बढ़ाया है।

एफएसडी की टीम ने छह सैंपल लिए

रुड़की। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने अलग-अलग स्थानों पर मिठाई की दुकानों जांच की। साथ ही छह मिठाई की सैंपल लिए। जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अभियान चलाया।

गोल्डनकार्ड की सुविधा ने देने से संगठन खफा

ऋषिकेश। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन शाखा ऋषिकेश ने अस्पतालों में गोल्डन कार्ड सुविधा नहीं मिलने के साथ अधिकारी-कर्मचारियों की उपेक्षा पर नाराजगी जताई है। चेताया कि सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में संगठन ने बैठक की। जिसकी अध्यक्षकता अभिषेक नवानी ने की। संघ ने गोल्डन कार्ड की विसंगतियों पर चर्चा की। अध्यक्ष अभिषेक नवानी ने कहा कि राज्य में वेतन से प्रत्येक माह कटौती के उपरांत भी संबंधित अस्पताल द्वारा गोल्डन कार्ड सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे न सिर्फ ऋषिकेश के बल्कि पूरे राज्य के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक परेशान है। संघ के शाखा सचिव थलवाल ने कहा कि एक तरफ तो सरकार कैशलैस सुविधा की बात कर रही है, जबकि वास्तविकता में गोल्डन कार्ड स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। संरक्षक वाईके घिल्डियाल ने कहा कि पुरानी पेंशन पुन: की भांति बहल की जाए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि एसीपी 10, 16, 26 में प्राप्त होनी चाहिए। सरकार को जल्द शासनादेश जारी करना चाहिए। उपाध्यक्ष एवं सलाहकार आरएस पंवार द्वारा सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक माह एक बैठक आयोजित की जाए।

देवेन्द्र जौहरी
सहसम्पादक
जतिन शर्मा
सहसम्पादक
विक्रान्त शर्मा
कानूनी सलाहकार
जसमहिन्द्र सिंह एडवोकेट

मोदी एक बार कह दें कि ट्रंप ने जंग नहीं रूकवाई

अजीत द्विवेदी

संसद के मानसून सत्र का इंतजार सबको था। इंतजार इसलिए था क्योंकि सरकार ने पहलगाम कांड और आपेरशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की अपील पर ध्यान नहीं दिया था। संसद में खड़े होकर विपक्ष को जवाब देने और देश के नागरिकों को इसकी सचाई बताने की बजाय सरकार दुनिया भर के देशों में डेलिगेशन भेज कर उनके सामने अपना पक्ष रख रही थी। तभी जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई और यह तय हुआ कि दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार, 28 जुलाई को पहलगाम कांड व आपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी तो उम्मीद थी कि इनसे जुड़े समूचे घटनाक्रम की सचाई सामने आएगी। सरकार हर पहलू के बारे में जानकारी देगी। विपक्ष जो सवाल पहले से उठा रहा है और जो सदन में सवाल उठाए जाएंगे, उनका वस्तुनिष्ठ तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि दो दिन की लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री के लंबे भाषण के बाद भी बहस अधूरी ही रह गई। इस बहस के बाद यह धारणा भी मजबूत हुई कि भारत में संसदीय बहसों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और सारी संसदीय बहस सिर्फ राजनीति साधने और चुनावी लाभ के लिए होती हैं। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में संसदीय बहसें ऐसी नहीं होती हैं। भारत में भी कोई संविधान सभा की बहस के दस्तावेज पढ़े तो उसे भी आज जो हो रहा है उस पर शर्म ही आएगी। बहरहाल, पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर से जुड़े कौन से सवाल थे, जिनके वस्तुनिष्ठ जवाब की जरुरत थी, उस पर आने से पहले एक रूपक के जरिए इस बहस को समझते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उनसे बिजली नहीं आने की शिकायत कर रहा था। वह व्यक्ति कह रहा था कि सिर्फ तीन घंटे बिजली आती है और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर तक यह बात सुनने के बाद माननीय बिजली मंत्री ने अपने गले में पड़ी ढेर सारी मालाएं निकालीं और जोर से नारा लगाया, जय श्रीराम! बात वही खत्म हो गई। लोकसभा में पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर पर सत्तापक्ष यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सभी नेताओं का भाषण इसी श्रेणी का था। सवालों का जवाब देने की बजाय सत्तापक्ष के लगभग सारे वक्ता सेना के शौर्य का गुणगान कर रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अपनी छाती ठोक रहे थे और 77 साल पहले वाली सरकार की कमियां गिना रहे थे। सोचें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब एक सौ मिनट के भाषण में 14 बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया! क्या पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा में देश के लोग यही सुनना चाहते थे? नेहरू की गलतियां थीं या इंदिरा गांधी ने गलती की या उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने गलतियां कीं तभी तो देश की जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी को मौका दिया है! अब तो देश के लोग इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। नेहरू का या इंदिरा गांधी का नाम लेकर किसी भी तात्कालिक मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। नेहरू की गलतियां अपनी जगह हैं, जिनके बारे में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक सौ साल से बोल रहे हैं। लेकिन लोग तो यह जानना चाहते थे कि पर्यटकों की उतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पहलगाम घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात था? लोग यह जानना चाहते थे कि आतंकवादी 2 मिनट तक तांडव करते रहे और उतनी देर में एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा और आतंकवादियों के जवाब देने के लिए एक भी गोली नहीं चली तो ऐसा क्यों हुआ? यह तो संभव नहीं है कि नेहरू या इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से रोक दिया था? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री के इतने लंबे भाषण में एक बार भी पहलगाम में मारे गए 26 बेकसूर नागरिकों का जिक्र नहीं आया। देश के लोग जानना चाहते थे कि आपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया तो फिर 88 घंटे के भीतर सीजफायर क्यों हो गया? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से गुहार लगाई कि पाकिस्तान अब और हमला नहीं झेल सकता है तो युद्धविराम हो गया। सवाल है कि पाकिस्तान मजबूर था कि वह हमारा हमला नहीं झेल पा रहा था लेकिन हमारी क्या मजबूरी थी? हमने क्यों सीजफायर स्वीकार कर लिया? अगर स्वीकार किया तो पाकिस्तान के सामने क्या शर्तें रखीं और क्या उसने हमारी कोई शर्त स्वीकार की? दुनिया के तमाम सामरिक और रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को दो तीन दिन और हमले जारी रखने चाहिए थे ताकि पाकिस्तान का सैन्य ढांचा स्थायी रूप से खत्म हो और उसके सैन्य नेतृत्व की कमजोरी पाकिस्तान की जनता के सामने जाहिर हो। लेकिन इसका उलटा हुआ। बिना शर्त युद्धविराम की वजह से पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को छाती ठोक कर जीत का दावा करने का मौका मिला और आज पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व पहले से ज्यादा मजबूती और ताकत के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में लगा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी उसकी प्रतिष्ठा कम होने की बजाय बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ कि भारत जीतता हुआ पक्ष था लेकिन उसने बिना शर्त सीजफायर कर लिया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सीजफायर कराने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने सीजफायर नहीं कराई। वे संसद में वही बोले, जो ब्राजील में जी 7 देशों के सम्मेलन में बोले थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी दोहराया कि अमेरिका के उप राष्ट्रपति जीडी वेंस ने उनसे कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है तो उन्होंने कहा कि हम उससे बड़ा हमला करेंगे। सवाल है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और हमें हमला करने की जरुरत नहीं पड़ी? कुछ तो हुआ परदे के पीछे, जिसके बाद सीजफायर हुआ! प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बताना चाहिए था कि क्या हुआ, जिसकी वजह से बिना शर्त सीजफायर की नौबत आई। विडम्बना यह है कि जिस समय प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रूकवाई लगभग उसी समय अमेरिका में ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रूकवाई। ध्यान रहे दुनिया का कोई नेता सीजफायर का श्रेय नहीं ले रहा है, सिर्फ ट्रंप ले रहे हैं। इसलिए दुनिया कि किसी नेता ने नहीं रूकवाई कहने की बजाय अगर प्रधानमंत्री मोदी एक बार कह दें कि ट्रंप ने जंग नहीं रूकवाई तो बात खत्म हो। लोग यह सुनना चाहते थे लेकिन यह नहीं कहा गया। एक और अहम बात जो पूरी चर्चा में मिसिंग रही वह ये है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। पेंसिल टूटने की बात कही गई लेकिन यह भारत के प्रतिरक्षा प्रमुख यानी सीडीसी जनरल अनिल चौहान की बात का स्पष्टीकरण नहीं है और न जकार्ता दूतावास के भारत के डिफेंसे अताशे कैप्टेन शिवकुमार की बात का जवाब है। दोनों ने भारत के नुकसान की बात कही थी। कैप्टेन शिवकुमार ने तो नुकसान के लिए राजनीतिक फैसले को जिम्मेदार बताया था। लेकिन पूरी बहस में सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया। भारत को कितना और क्या नुकसान हुआ यह बताया जाना चाहिए था या फिर यह कहा जाना चाहिए था कि सेना के दोनों अधिकारियों ने जो कहा वह सही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीमित जंग में चीन सक्रिय भागीदार था और यह बात भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। उसने पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ अपने हथियारों का परीक्षण किया। भारत के खिलाफ युद्ध में चीन की सक्रिय भागीदारी के बावजूद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों चीन के दौरे पर गए और जब आपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हुई तो उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह सही है कि इतने बड़ा घटनाक्रम के बावजूद भाजपा और नरेंद्र मोदी को कोई राजनीतिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है। लेकिन समर्थक वर्ग को परवाह नहीं है क्या इस वजह से इतने अहम सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा?

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नया तनाव

विनीत नारायण

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ और रूस से तेल और हथियारों की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की घोषणा की। यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में महत्त्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस को मृत अर्थव्यवस्था (डेड इकानमी) कह कर निशाना बनाया और भारत के उच्च टैरिफ और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं को इसका कारण बताया। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाली आक्रामक टैरिफ नीतियों को अपनाया है। 7 अगस्त, 225 से लागू होने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने इसके लिए भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार, भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, जो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के समय में अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ (जिसे उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक बताया) और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं की भी आलोचना की। ट्रंप ने पहले 2-25 प्रतिशत टैरिफ की संभावना जताई थी, लेकिन अंतिम घोषणा में अतिरिक्त दंड भी शामिल किया गया। यह कदम भारत के फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, र प्रतिशत और आभूषण और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। कांग्रेस नेता और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, हां, ट्रंप सही हैं। हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। मुझे खुशी है कि ट्रंप ने यह तथ्य सामने रखा। दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। भाजपा ने अडानी को मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। राहुल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी अर्थव्यवस्था के पतन के कारण बताए। उन्होंने यह भी पूछा कि ट्रंप के भारत-पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बार-बार किए जा रहे दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने इस टैरिफ को भारत की विदेश नीति की विफलता के रूप में चित्रित किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी। यह टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर असर डालेगा। हम अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करते हैं, और 25 प्रतिशत टैरिफ से ये महंगे हो जाएंगे जिससे मांग कम होगी और उत्पादन तथा रोजगार पर असर पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और टैरिफ को भारत के व्यापार, एमएसएमई और किसानों के लिए हानिकारक बताया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरे दिनों की शुरुआत बताया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रंप को व्हाइट हाउस का जोकर कह कर उनकी आलोचना की। वहीं, अर्थशास्त्रियों ने इस टैरिफ के भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर मिश्रित राय व्यक्त की है। कुछ का मानना है कि इसका प्रभाव सीमित होगा जबकि अन्य ने दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी दी है। इंवेस्टमेंट इनफार्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया (इक्रा) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, प्रस्तावित टैरिफ और दंड हमारी अपेक्षा से अधिक हैं, और इससे भारत की जीडीपी की वृद्धि पर असर पड़ सकता है। प्रभाव की गंभीरता दंड के आकार पर निर्भर करेगी। अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया (ईवाई) के व्यापार नीति विशेषज्ञ अग्नेर सेन ने कहा, टैरिफ से समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, चमड़ा और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ये क्षेत्र भारत-अमेरिका व्यापार में मजबूत हैं, और टैरिफ से इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। फाउंडेशन फार इकोनामिक डवलपमेंट के राहुल अहलूवालिया ने चेतावनी दी कि टैरिफ भारत को वियतनाम व चीन जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कमजोर कर सकता है।

राखी, राहत और रिश्ता : आपदा के बीच मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक दृश्य

जतिन शर्मा

धराली (उत्तरकाशी)/देहरादून। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को एक अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दीं। गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईशनपुर निवासी धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आई थीं। 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के कारण वे धराली में अपने परिवार सहित फंस गईं। मार्ग अवरुद्ध होने और लगातार मलबा व तेज बहाव के कारण स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत व बचाव कार्य प्रारंभ किए गए। मुख्यमंत्री स्वयं तीन दिनों से लगातार क्षेत्र में मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों के अथक प्रयासों से श्रीमती बरौलिया और उनके परिवार को सुरक्षित निकाला गया। रक्षाबंधन से पहले दिन जब मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे, तब श्रीमती बरौलिया ने भावुक होकर अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उसे राखी के रूप में मुख्यमंत्री श्री धामी को बांधा। यह दृश्य वहां उपस्थित सभी लोगों को गहराई से छू गया। मुख्यमंत्री ने भी इस भावनात्मक क्षण को विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। धराली जैसे दुर्गम क्षेत्र में मानवीय संवेदनाओं का यह दृश्य विपदा के बीच आशा, विश्वास और सामाजिक एकजुटता की मिसाल बना।

राहुल खन्ना बने बजरंग दल चमोली के विभाग संयोजक

रुद्रप्रयाग। विश्व हिन्दू परिषद उत्तराखंड की प्रान्तीय बैठक में रुद्रप्रयाग में बजरंग दल के सक्रिय युवा राहुल खन्ना को चमोली जनपद का विभाग संयोजक बनाया गया है। अन्य सदस्यों से भी दल के लिए बेहतर कार्य करने का आह्वान किया गया है। ऋषिकेश बैठक से लौटे पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन के प्रान्तीय एवं अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारियों की मौजदूगी में संगठन के विस्तार, भविष्य की कार्ययोजनाओं, सामाजिक जिम्मेदारियों एवं सेवा कार्यों को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक सशक्त, अनुशासित व प्रभावी बनाना रहा है। जिसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमें संगठनात्मक नियुक्तियां भी शामिल थी। विशेष रूप से राहुल खन्ना को बजरंग दल चमोली का विभाग संयोजक नियुक्त किया जाना पूरे प्रदेश के लिए बड़ी बात है। पदाधिकारियोंने बताया कि राहुल खन्ना बीते कई वर्षों से बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनके कार्यों की विशेषता गौ-संरक्षण, आपदा राहत कार्य, युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना, धर्मांतरण विरोधी गतिविधियों में सहभागिता एवं सेवा कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाना रही है। वे न केवल संगठनात्मक गतिविधियों में समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं बल्कि जनसेवा की भावना से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने समय-समय पर दूरस्थ क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने, रक्तदान शिविर आयोजित करने और हिंदू संस्कार शालाओं के संचालन में भी योगदान दिया है। बैठक में आशुतोष नेगी को विश्व हिन्दू परिषद रुद्रप्रयाग का जिला मंत्री नियुक्त किया गया। आशुतोष नेगी भी लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं जबकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में उनकी सहभागिता सराहनीय रही है।

धराली आपदा के घायल, कुछ को एम्स में मिला स्वास्थ्य लाभ

जतिन शर्मा

ऋषिकेश। धराली आपदा के 3 घायलों में से 2 लोगों को शुक्रवार को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि एक घायल का एम्स के ट्रॉमा सेन्टर में उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उपचाराधीन घायल की स्थिति में सुधार है। उत्तरकाशी के धराली में आयी आपदा के 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। आवश्यक उपचार के बाद इनमें से 2 घायलों राम प्रताप और शिवांशु को बुद्धवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। संस्थान के जन संपर्क अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि डिस्चार्ज किए गए दोनों लोग सेना के जवान हैं और उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। उन्होंने बताया कि ट्रॉमा चिकित्सकों के अनुसार उपचार हेतु भर्ती तीसरे घायल वीरेन्द्र का ट्रॉमा इमरजेन्सी में इलाज जारी है। वीरेन्द्र की हालत में सुधार है और ट्रॉमा चिकित्सक उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

रानीपुर विधानसभा में तीन सड़क निर्माण को 2.32 करोड़ रुपए की मिली शासन से वित्तीय स्वीकृति

जतिन शर्मा

हरिद्वार। उत्तराखंड शासन ने हरिद्वार जनपद की बी.एच.ई.एल रानीपुर विधानसभा में राज्य योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के तीन कार्यों के लिए 232.64 लाख रुपये की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिसका जीओ जारी कर दिया गया है । सरकार ने सड़क निर्माण के लिए 3, रुपये की टोकन राशि भी जारी कर दी है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान के प्रस्ताव पर राज्य योजना से विधानसभा के अंतर्गत नगरपालिका शिवालिकनगर के वार्ड-13 के केशवनगर में आंतरिक गलियों की इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य, रोशनाबाद की आंतरिक गलियों की इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य और ग्रामसभा रावली महदूद की आंतरिक सड़कों का इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य किया जाना है। योजना के अन्तर्गत कुल 2.5 किमी सड़क निर्माण किया जाना है। निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया है। सरकार द्वारा शासनादेश पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रदेश के लिए विकासपरक सोच से ही विकास कार्य धरातल पर तेजी से आ रहे हैं। क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है सरकार की विभिन्न योजनाओं से पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्रगति पर हैं भाजपा शासन काल में रानीपुर विधानसभा में विकास की नई गाथा लिखी है। उक्त सड़को की टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

काठगोदाम में नए एजीएम गणेश पंत का स्वागत

हल्द्वानी। उत्तराखंड परिवहन निगम में काठगोदाम डिपो के सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) गणेश पंत ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै ने सहायक महाप्रबंधक से काठगोदाम डिपो की दो वाल्वो बसें ऑनलाइन करने, डग्गामारी रोकने, कर्मचारियों के साथ आपसी मेलजोल से निगम की आय बढ़ाने पर चर्चा की। सहायक महाप्रबंधक पंत ने यूनियन को भरोसा दिया कि सभी से मिलजुलकर निगम हित में कार्य करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष आनंद बिष्ट, शाखा अध्यक्ष मनोज भट्ट, शाखा मंत्री शशिकांत गौतम, कैलाश कांडपाल, रेहान अली, जहांगीर खां आदि मौजूद रहे।

उद्घाटन मैच में द दून स्कूल ने मेयो कॉलेज को दी शिकस्त

विक्रासनगर। सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हो रहे 10वें ऑल इंडिया इंटर-स्कूल इनविटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट (अंडर-19 बॉयज) का उद्घाटन मैच दून स्कूल ने जीता। दून स्कूल ने मेयो कॉलेज को शिकस्त दी। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन आदित्य बख्शी ने प्रतिभागी स्कूलों का स्वागत किया गया। उन्होंने सभी टीमों को खेल भावना और दोस्ती के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस वर्ष टूर्नामेंट में देशभर के प्रतिष्ठित स्कूल भाग ले रहे हैं। जिनमें द दून स्कूल देहरादून, वेल्हम बॉयज स्कूल देहरादून, लॉरेंस स्कूल सनावर, सागर स्कूल अलवर, मेयो कॉलेज अजमेर, कासिगा स्कूल देहरादून, जीआरडी वर्ल्ड स्कूल भाऊवाला देहरादून और मेजबान सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन डॉ. दिलीप पांडा ने किया। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला द दून स्कूल देहरादून और मेयो कॉलेज अजमेर के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में द दून स्कूल के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक
देवेन्द्र जौहरी द्वारा
साप्ताहिक समाचार पत्र
''गुरुकृपा दर्पण'' को
रूद्र प्रिंटिग प्रेस, ई-34,
ओल्ड इड्रस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार
(उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं
एस-3, अशोक विहार कालोनी,
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
से प्रकाशित।
सम्पादक: **देवेन्द्र जौहरी**
मो. – **9997331129**
E-mail :
gurukripadarpan@gmail.com